



दिनांक/Dated: 05.05.2020

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 12.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7/5/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी MoP, PG&P, Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No. 7/5/2012-P&PW(F)/B dated 12.02.2020	राज्य सरकार/केंद्र सरकार/ स्वायत्त निकाय में नई सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपदान के लाभ के लिए सेवा की संगणना। Counting of service on joining new service in State Government / Central Government / autonomous body for the benefit of gratuity in respect of Central Govt. Employees covered under National Pension System (NPS).
2.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं० 57/04/2019- पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी MoP, PG&P, Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No. 57/04/2019- P&PW(F)/B dated 17.02.2020	Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules 1972, in place of National Pension System, of those Central Government employees whose selection for appointment was finalized before 01.01.2004 but who joined Government service on or after 01.01.2004

भवदीय/Yours faithfully

बी.के.सिंह/B.K. Singh)

उप सचिव (नीति प्रभाग)/DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

- 1 -
सं. 7/5/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली दिनांक 12 फरवरी, 2020

कार्यालय जापन

विषय : राज्य सरकार/केंद्र सरकार/स्वायत्त निकाय में नई सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपदान के लाभ के लिए सेवा की संगणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय जापन सं. 38/41/06-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के द्वारा सेवा के दौरान मृत्यु/निःशक्तता होने पर अशक्तता/निःशक्तता पेंशन, कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के लाभ दिनांक 01.01.2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों के सममूल्य पर एनपीएस कर्मचारियों को भी अनंतिम रूप से दिए गए थे। तत्पश्चात्, इस विभाग के दिनांक 26.08.2016 के का. जा. सं. 7/5/2012-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)/बी के द्वारा सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के लाभ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उन्हीं नियम एवं शर्तों पर दिए गए, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित कर्मचारियों पर लागू हैं।


2. एक संगठन से दूसरे संगठन में जाने पर सेवानिवृत्ति उपदान के लाभ के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए इस विभाग में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर व्यय विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपदान की संस्वीकृति एवं उचित अनुमति सहित अन्यत्र पदस्थापन होने पर उपदान के लिए सेवा की गणना निम्न तरीकों से विनियमित की जा सकती है:-

- (i) केंद्र सरकार की सेवा से अन्य केंद्र सरकार सेवा में जाने पर केंद्र सरकार के पिछले विभाग में दी गई सेवा की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। केंद्र सरकार के दो विभागों के बीच उपदान की पात्रता के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी।
- (ii) केंद्र सरकार की सेवा से केंद्र सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वाली राज्य सरकार में जाने पर, केंद्र सरकार में दी गई सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। वही प्रावधान केंद्र सरकार के विभाग में जाने पर राज्य सरकार के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच उपदान की पात्रता के लिए कोई साझेदारी नहीं होगी।

- (iii) केंद्र सरकार की सेवा से केंद्र सरकार की तरह ही अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले केंद्र या राज्य स्वायत्त निकायों में जाने पर, केंद्र सरकार में दी गई सेवाओं की उपदान की देयता के लिए गणना की जाएगी। सरकार में दी गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान की राशि केंद्र या राज्य स्वायत्त निकायों को देकर सरकार द्वारा उपदान की जिम्मेदारी वहन की जाएगी। यही प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले कर्मचारी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी, जो एक स्वायत्त निकाय से दूसरी स्वायत्त निकाय या एक स्वायत्त निकाय से केंद्र सरकार/विभाग/संगठन, यदि दोनों ने केंद्र सरकार की तरह अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना अपनाया है, में जाते हैं।
- (iv) केंद्र सरकार से केंद्र या राज्य के स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार में जाने पर जहां केंद्र सरकार की तरह उपदान देने का प्रावधान नहीं है या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में जाने पर राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले सरकारी कर्मचारी को केंद्र सरकार में दी गई सेवा के लिए नियमानुसार सेवानिवृत्ति उपदान दी जाएगी, बशर्ते भारत सरकार और बाद के संगठन में दी गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य कुल उपदान उस स्वीकार्य राशि से ज्यादा नहीं होगा, जो अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा जारी रखता और बाद के संगठन से सेवानिवृत्ति पर आहरित वेतन के समान वेतन पर सेवानिवृत्त होता।

ऊपर के प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो केंद्र/राज्य सरकार या केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अन्य नियुक्ति लेने हेतु उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र देते हैं।

3. यह व्यवस्था विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.10.2019 के यू.ओ. नोट सं. 1(4)/ईवी/2006-II के तहत सहमति द्वारा जारी किया जाता है।
4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू, इन आदेशों को भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किया गया है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत अधिदेशाधीन है।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेश उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी कार्यालयों/क्षेत्र गठनों को अवगत कराएं।


(रुचिर मिश्र)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

No. 7/5/2012-P&PW(F)/B
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 12th February, 2020.

OFFICE MEMORANDUM.

Subject: Counting of service on joining new service in State Government / Central Government / autonomous body for the benefit of gratuity in respect of Central Govt. Employees covered under National Pension System (NPS).

The undersigned is directed to say that vide this Department's O.M. No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009, in the event of death / disability during service, the benefits of Invalid / Disability pension, Family pension and retirement / death gratuity were provisionally extended to NPS employees at par with the employees appointed before 01.01.2004. Subsequently, the benefit of retirement gratuity and death gratuity has been extended to all Central Government employees covered under National Pension System (NPS) vide this Department's OM No. 7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016 on the same terms and conditions, as are applicable to employees covered by CCS (Pension) Rules, 1972.

2. References have been received in the Department seeking clarification with regard to the benefit of retirement gratuity on mobility from one organization to another organization. This matter has been considered in consultation with Department of Expenditure. It has been decided that the grant of retirement gratuity and counting of service for gratuity on mobility of an NPS Government employee may be regulated in the following manner:

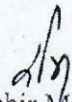
- (i) On mobility from a Central Government service to another Central Government service, the service rendered in the previous Department in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. There shall be no sharing of gratuity liability between the two Departments of Central Government.
- (ii) On mobility from a Central Government service to a State Government service having National Pension System with provision for Retirement / Death Gratuity for its employees similar to those in Central Government, the service rendered in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. Same provisions shall apply on mobility of an NPS employees of the State Government to Central Government Department. There shall be no sharing of gratuity liability between the Central and State Governments.

Contd..2/.

- (iii) On mobility from Central Government service to a Central or State Autonomous Body service having National Pension System with provision of retirement / death gratuity for its employees similar to that in the Central Government, the service rendered in the Central Government would be counted for grant of gratuity. The Government will discharge its gratuity liability by paying the amount of retirement gratuity for the service rendered in the Government to the Central or State Autonomous body. This procedure shall be followed mutatis mutandis in respect of NPS employees going over from one autonomous body to another autonomous body or from an autonomous body to Central Government / Department / organisation both having National Pension System with provision of retirement / death gratuity for its employees similar to that in the Central Government.
- (iv) On mobility from Central Government service to a Central or State Autonomous Body or to a State Government where the provision for grant of gratuity similar to that in Central Government does not exist or to a Public Sector Undertaking, the NPS Government employees shall be granted retirement gratuity as per rule for the service rendered in the Central Government subject to the condition that the total gratuity admissible in respect of the service rendered under the Government of India and that under the later organization, shall not exceed the amount that would have been admissible, had Government servant continued in Government service and retired on the same pay which he/ she drew on retirement from the later Organization.

The above provisions would be applicable to Government employees covered under NPS who resign to take up with proper permission, another appointment in the Central / State Government or Central / State Autonomous body or a PSU.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their U.O. Note No. 1(4)/EV/2006-II Dated 30.10.2019.
4. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.
5. All the Ministries / Departments are requested to bring the above instruction to the notice of all offices / field formation working under their administrative control.


(Ruchir Mittal)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries / Departments of the Government of India.

No. 57/04/2019-P&PW(B)
Government of India
Department of Pension and PW

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 17th February, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in place of National Pension System, of those Central Government employees whose selection for appointment was finalized before 01.01.2004 but who joined Government service on or after 01.01.2004.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 1.1.2004 requesting for the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on the ground that their appointment was delayed on account of administrative reasons or lapses. Similar references have been received from Ministries/Departments seeking advice of this Department on the question whether the Government servants who were appointed on or after 1.1.2004 could also be extended the benefit of pension scheme under CCS (Pension) Rules, if their appointment was delayed beyond 31.12.2003 on account of administrative reasons and the delay in appointment was beyond the control of the said Government servants.

3. From the representations of the Government employees and the references received from Ministries/Departments, it has been observed that in many of the cases referred to this Department, selection process (including written examination, interview and declaration of result) for recruitment had been completed before 01.01.2004 but the employee joined the Government service on or after 01.01.2004. A few illustrations where the selection was finalized before 01.01.2004 but actual joining took place on or after 01.01.2004 are as under:

(i) The result for recruitment was declared before 01.01.2004 but the offer of appointment and actual joining of the Government servant was delayed on account of police verification, medical examination etc.;

-2-

(ii) Some of the candidates selected through a common selection process were issued offers of appointments and were also appointed before 01.01.2004 whereas the offers of appointment to other selected candidates were issued on or after 01.01.2004 due to administrative reasons/constraints including pending Court/CAT cases.

(iii) Candidates selected before 01.01.2004 through a common competitive examination were allocated to different Departments/organization. While recruitment process was completed by some Department(s) / organizations on or before 31.12.2003 in respect of one or more candidates, the offers of appointment to the candidates allocated to the other Departments / organization were issued on or after 01.01.2004.

(iv) Offers of appointment to selected candidates were made before 01.01.2004 with a direction to join on or after 01.01.2004.

(v) Offers of appointment were issued to selected candidates before 01.01.2004, and many/most candidates joined service before 01.01.2004. However, some candidate(s) were allowed extension of joining time and they joined service on or after 01.01.2004. However, their seniority was either unaffected or was depressed in the same batch or to a subsequent batch, the result for which subsequent batch was declared before 01.01.2004.

(vi) The result for recruitment was declared before 01.01.2004 but one or more candidates were declared disqualified on the grounds of medical fitness or verification of character and antecedents, caste or income certificates. Subsequently, on review, they were found fit for appointment and were issued offers of appointment on or after 01.01.2004.

In all the above illustrative cases, since the result for recruitment was declared before 01.01.2004, denial of the benefit of pension under CCS (Pension) Rules, 1972 to the affected Government servants is not considered justified.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has been decided that in all cases where the results for recruitment were declared before 01.01.2004 against vacancies occurring on or before 31.12.2003, the candidates declared successful for recruitment shall be eligible for coverage under the CCS(Pension) Rules, 1972. Accordingly, such Government servants who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies occurring before 01.01.2004 and are covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given

a **one-time option** to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972. This option may be exercised by the concerned Government servants **latest by 31.05.2020.**

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. It is clarified, that the above option would be available to only those Government servants who were declared successful for recruitment before 01.01.2004, against vacancies pertaining to the period prior to that date. This option shall, however, not be available to the Government servants appointed on or after 01.01.2004 if they fall in any of the following categories:

(i) Government servants whose names were included in a panel of selected candidates before 01.01.2004 for recruitment against vacancies occurring on or after 01.01.2004 and were, accordingly, recruited on or after 01.01.2004.

(ii) A Government servant whose name was included in a panel of selected candidates prepared before 01.01.2004 for vacancies arising before and after 01.01.2004 but was actually appointed after 31.12.2003 against a vacancy arising on or after 01.01.2004.

(iii) Government servants who were selected against vacancies pertaining to the period prior to 01.01.2004 on the basis of an advertisement/notification issued before 01.01.2004 or a written examination/interview held before 01.01.2004 but results for recruitment were declared on or after 01.01.2004.

(iv) Government servants who joined on or after 01.01.2004 after they were granted extension of joining time on their own request and, in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel & Training, their seniority was depressed on account of such extension of joining time to a batch for which the result for recruitment was declared on or after 01.01.2004.

8. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 based on the option exercised by the Government servant shall be placed before the appointing authority for consideration in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfils the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972, in accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by **30th September, 2020.** The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. **01st November, 2020.**

9. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972, shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding account of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cia./TA III/390 dated 14.11.2019:

- i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts:** Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 & Rule 11 of GPF Rules).
- ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts:** To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of overpayment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).
- iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** - May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800- Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA).

10. **All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders.** The cases of those Government servants who fulfil the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

11. These orders issue with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their I.D. Note No. 1(7) EV/2019 dated 08.01.2020.

12. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

13. Hindi version will follow.


(Ruchir Mittal)

Deputy Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Govt. Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
8. AD(OL) for Hindi version.
9. NIC for posting on the website of this Department.